वर्ष 2008-09 में 7.4 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल

सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने का संकल्प

प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष से सोलन ज़िला की टमाटर तथा कांगड़ा एवं ऊना ज़िलों की आलू की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया है। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृषि विकास अधिकारियों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों के 400 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 295 अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। शेष पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

बागबानी उत्पादों के लाभकारी मूल्य के लिए मंडी मध्यस्थता योजना

बागबानी प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मुख्य आधार है तथा बागबानी उत्पाद को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने बागबानी विकास गतिविधियों को सुदृढ़ किया है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 2.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागबानी के अन्तर्गत लाया गया है तथा प्रदेश ने रिकार्ड फल उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 से 5000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागबानी के अन्तर्गत लाया जा रहा है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था में बागबानी उद्योग का लगभग दो हजार करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान है। सरकार ने राज्य विपणन नीति को सुदृढ़ किया है तथा मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत खरीदे जा रहे सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है। प्रदेशभर में बागबानी तकनीकी मिशन को अक्तूबर 2003 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक भारत सरकार से 128.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस मिशन के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश के 1 लाख 2 हजार 199 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' जैसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश में बागबानी गतिविधियों को और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 1354 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। फल उत्पादन, उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने और सेब, नाशपाती, गुठलीदार फलों तथा गिरीदार फलों के जर्मप्लाज़्म में सुधार लाने के लिए उनका आयात करके सरकारी नर्सरियों में तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिवर्ष फसलों को भारी नुकसान होता है। प्रदेश सरकार ने पायलट आधार पर सेब तथा आम के लिए **'मौसम आधारित फसल बीमा योजना'** आरम्भ की है जिसके लिए किसानों को सरकार प्रीमियम के हिस्से के रूप में 50 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है।

300 करोड़ की दूध गंगा योजना

पशुधन प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश में 2133 वेटनरी संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। पशुधन में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पशुधन उत्पादन में वृद्धि के प्रति लक्षित विभिन्न गतिविधियां जैसे वेटनरी सेवाएं, टीकाकरण, पशुचारा विकास आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के मण्डी, सोलन तथा सिरमौर जिलों में 300 करोड़ रुपये की **'दूध गंगा योजना'** आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अथवा स्वयं सहायता समूह द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। इसमें से 50 प्रतिशत ऋण ब्याजमुक्त है तथा ऋण की समय पर अदायगी की स्थिति में 50 प्रतिशत ब्याज पर उपदान भी दिया जा रहा है। किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमीरपुर तथा शिमला ज़िलों में दुधारू पशु बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में भेड़पालकों की स्थिति में सुधार के लिए भेड़पालक बीमा योजना संचालित की जा रही है तथा इस योजना के अन्तर्गत 8993 भेड़पालकों का बीमा किया गया है। आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए कांगड़ा ज़िला के खजियां में 175 लाख रुपये की लागत से 600 पशुओं की क्षमता वाले गौसदन का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सोलन, हमीरपुर तथा बिलासपुर ज़िलों के पांच गौसदनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 187 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। गौसदनों को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 56 गौसदनों में वर्मी कम्पोस्ट गड्ढों के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से दूध के खरीद मूल्य में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दूध को ग्राम स्तर पर ही तुरन्त शीतलीकरण हेतु प्रदेशभर में 52 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। दुग्ध जांच में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम डेयरी सहकारी समितियों में 6 स्वचलित दुग्ध एकत्रीकरण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

प्रदेश में मत्स्य पालन को उचित प्राथमिकता दी जा रही है। कारगर विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के जलाशयों में 538 लाख रुपये मूल्य की 1063 टन मछलियों का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इस अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 99 टन अधिक है। प्रदेश के 6560 मछुआरों को प्रीमियम–मुक्त बीमा कवर प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बीमा कवर की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

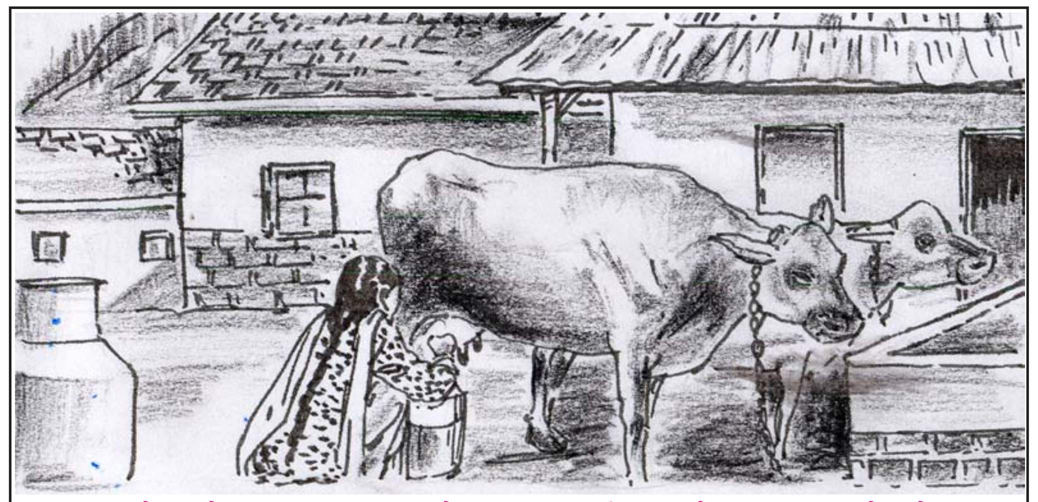

"कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के मण्डी, सोलन तथा सिरमौर जिलों में 300 करोड़ रुपये की 'दूध गंगा योजना' आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अथवा स्वयं सहायता समूह द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। इसमें से 50 प्रतिशत ऋण ब्याजमुक्त है तथा ऋण की समय पर अदायगी की स्थिति में 50 प्रतिशत ब्याज पर उपदान भी दिया जा रहा है।"

139 गांवों को सड़क सुविधा

मेरी सरकार ने नई सड़कों के निर्माण तथा मौजूदा सड़कों के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की कुल लम्बाई 31,328 किलोमीटर है। कुल 17,449 जनगणना गांवों में से 9382 गावों को वाहन योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 611 किलोमीटर मोटरयोग्य नई सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है तथा 139 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 2947 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है जबकि 259 पंचायतों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 1472 किलोमीटर है। प्रदेश में कुल 890 किलोमीटर लम्बाई के 7 अन्य राज्य मार्गों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य में 2435 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गो के उन्नयन एवं सुधार के लिए 1365 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित राज्य सड़क परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। मेरी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 145.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से होली–उत्तराला सुरंग, 85.75 करोड़ रुपये से करसेहड से तेलंग (भूबू जोत) सुरंग तथा 35.40 करोड़ रुपये की बंगाणा–धनेटा सुरंग का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इन सुरंगों के निर्माण से न केवल इन क्षेत्रों में दूरी कम होगी बल्कि इनसे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।

उच्च शिक्षा के लिए 615 करोड़

मेरी सरकार का प्रयास प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का है। प्रदेश ने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तथा मैदानी क्षेत्रों में डेढ़ से तीन किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक /प्रारम्भिक पाठशालाएं खुलने से प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच मज़बूत हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 10727 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 4383 माध्यमिक पाठशालाएं कार्यरत है तथा 88 शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक नवीन शिक्षा केन्द्र तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलित केन्द्र भी घुमन्तू जनसंख्या को शिक्षा प्रदान कर रहे है। प्रारम्भिक पाठशालाओं में न्यूनतम तीन कमरों की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश की सभी राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं में खेल मैदान, पेयजल तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

'मध्याह्न भोजन योजना' पूरे प्रदेश में माध्यमिक स्तर तक सन्तोषजनक तरीके से संचालित की जा रही है जिससे प्राथमिक पाठशालाओं के 4 लाख 70 हजार 630 बच्चे तथा अप्पर प्रारम्भिक पाठशालाओं के 3 लाख 39 हजार 604 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश में विकलांग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के चम्बा, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर ज़िलों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े आठ खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों एवं समाज के सभी वर्गो के लिए उसकी समान पहुंच को सुनिश्चित बनाया जा सके। कुल योजना आबंटन तथा शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007 से 12 की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र के लिए 14 हज़ार करोड़ रुपये का कुल योजना आबंटन किया गया है जिसमें से उच्च शिक्षा के लिए 615.15 करोड़ रुपये आबंटित किए गये है। मेरी सरकार प्रदेश के लोगों की बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करती रहेगी।

मेधावी तथा कमज़ोर वर्गो के विद्यार्थियों सहित विभिन्न श्रेणियों के अनेक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए इस समय प्रदेश में 14 छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा वर्ष 2009–10 के दौरान इन पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. वर्गो के छठी से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान इस पर 8.85 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं जिससे नौवीं तथा दसवीं कक्षा के 1 लाख 18 हजार 166 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। कालेज प्रवक्ताओं के 634 पद, स्कूल प्रवक्ताओं के 1140 पद तथा सहायक लाईब्रेरियन के 82 पद सीधी भर्ती द्वारा, भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत स्कूल प्रवक्ताओं के 185 पद सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा प्रधानाचार्यो के 16 पद पदोन्नति द्वारा तथा कालेज केडर के प्रधानाचार्यो के पांच पद सीधी भर्ती द्वारा, 218 प्रवक्ताओं (कालेज केडर), 302 प्रिंसीपल (स्कूल केडर) तथा मुख्य अध्यापकों के 862 पद भरे गए हैं।

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सतत् विकास के लिए ऐसी सशक्त तकनीकी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें श्रेष्ठता, प्रासंगिकता एवं सहभागिता केन्द्र बिन्दु हों और यह प्रणाली रोज़गार अवसरों की वैश्विक उपलब्धता एवं राज्य आर्थिकी की वृद्धि के प्रति समर्पित एवं लक्षित हो। सरकारी क्षेत्र में आगामी शैक्षणिक सत्र से हमीरपुर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। **'दक्षता विकास के लिए समन्वयिक कार्य के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ पॉलीटेक्नीक'** योजना के अन्तर्गत बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति ज़िलों में पांच नए पॉलीटेक्नीक खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है जिसमें प्रत्येक पॉलीटेक्नीक के लिए एक मुश्त 12.3 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान का प्रावधान है। प्रदेश की तीन आई.टी.आई को डोमेस्टिक वित्तपोषण योजना के तहत अपग्रेड किया गया है तथा प्रदेश की 11 आई.टी.आई. को विश्व बैंक की सहायता से 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया गया है।

समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए है। 2 लाख 67 हजार 288 लाभार्थियों को 330 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।

घर–द्वार तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

मेरी सरकार प्रदेश के लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शिमला में एम.बी.बी.एस. की सीटों को 65 से बढ़ाकर 100 तथा पोस्टग्रेजुएट सीटों को 39 से बढ़ाकर 62 किया गया है। पोस्टग्रेजुएट में 21 अतिरिक्त सीटें जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है। प्रदेश सरकार ने डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा में नर्सिंग शिक्षा में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने का निर्णय लिया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना–II के अन्तर्गत अपग्रेड करने के लिए चयनित किया गया है जिसके लिए भारत सरकार 125 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपये का योगदान देगी। प्रदेश में मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए छ: आवेदकों को 'लैटर ऑफ इंटेंट' जारी किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 254 चिकित्सा अधिकारियों तथा 605 नर्सों की नियुक्ति की गई है तथा उन्हें प्रदेश के दूर–दराज एवं कठिन क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार ने 568 संस्थानों में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक) रोगी कल्याण समितियों का गठन किया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकेन्द्रीकृत रूप में कारगर प्रबन्धन किया जा सके। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आपातकाल के समय तथा रेफरल परिवहन के लिए सभी उपकरणों से लैस 100 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाकर राज्य में एमरजैंसी मेडिकल रिस्पोंस सिस्टम की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित किया गया है जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को 80,242 स्मार्ट कार्ड जारी किये गए हैं ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी विभाग द्वारा भी प्रदेश में 25 आयुर्वेदिक अस्पतालों, 1109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 14 होम्योपैथी केन्द्रों, 3 यूनानी केन्द्रों, 4 आमची एवं एक नेचर केयर इकाई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है । आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 85 पद भरे गए हैं तथा 300 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम को प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित किया गया तथा अनीमिया की जांच के लिए रक्त के 8 लाख 98 हजार 491 नमूने लिए गए। योग तथा आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोलन ज़िले की कंडाघाट तहसील के मौज़ा–कहलोग में 96.02 बीघा भूमि औषधीय पौधों तथा जड़ी–बूटी उगाने के लिए पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार को उपलब्ध करवाई गई जो प्रदेश को हर्बल राज्य बनने में सहयोग देगा। पतंजलि योग पीठ के साथ औषधीय पौधों की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश में औषधीय पौध क्षेत्र के विकास के लिए 7.56 करोड़ रुपये की कार्य योजना राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड, भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

स्वच्छ पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी जनगणना गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान कर दी गई है तथा अब प्रदेश की सभी बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित 5 हज़ार बस्तियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति 3854 बस्तियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न भागों में 1591 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं। धर्मशाला तथा सुन्दरनगर की पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संवर्द्धन कार्य तथा कोटखाई एवं सुन्नी की मल निकासी योजनाओं को इसी वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बेहतर कर–प्रशासन तथा मौजूदा कानूनों के कारगर अनुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। व्यापारी कल्याण परिषद स्थापित की गई है। वेट कम्प्यूटरीकरण परियोजना पर कार्य आरम्भ किया गया है जिसके वर्तमान वर्ष के दौरान आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रति कटिबद्ध है। पंचायत घर के निर्माण लागत के मानकों को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.40 लाख रुपये किया गया है तथा 238 नए पंचायत घरों के निर्माण के लिए 499.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। 730 पंचायत घरों को अपग्रेड करने पर 730 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। गत दो वर्षो के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के 21,238 निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 106.76 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। शेष बची 873 ग्राम पंचायतों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध हो सके।

मेरी सरकार द्वारा निर्धन बेघर लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न आवास योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत 8212 नए घरों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति 1768.68 लाख रुपये की लागत से 4222 घरों का निर्माण किया गया है। **'अटल आवास योजना'** के तहत 5175 नए घरों के लक्ष्य के प्रति 2314 घरों का निर्माण किया गया है जिन पर 1196.18 लाख रुपये व्यय किये गये तथा सभी निर्मित घर लाभान्वितों को स्वीकृत किये जा चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना' चलाई जा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जा रहे है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जिलों के अग्रणी बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जा सके। **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'** (मनरेगा) के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक **'राज्य रोजगार गारंटी निधि'** में 331.78 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से तथा 26 करोड़ रुपये राज्य हिस्से के रूप में जमा किये गये हैं। दिसम्बर, 2009 तक 352.68 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। राज्य में 180 लाख श्रम दिवसों का सृजन कर 3 लाख 93 हजार 83 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में **'जलागम विकास कार्यक्रम'** को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर 2009 तक विभिन्न जलागम विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 325.51 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के लिए कुल 305.75 करोड़ रुपये लागत की 36 नई परियोजनाएं स्वीकृत की है जिसके तहत राज्य के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में 4 से 7 वर्षो की अवधि में 2 लाख 3 हजार 832 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जायेगा।

स्कूल स्वच्छता पुरस्कार योजना आरंभ

'महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार योजना' के तहत राज्य की स्वच्छतम ग्राम पंचायतों को इस वर्ष 144 लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में जारी किये गये है। 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' के तहत गांवों, वार्डो तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले महिला मण्डलों को 95.50 लाख रुपये की राशि जारी की जा रही है। मेरी सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए 'स्कूल स्वच्छता पुरस्कार योजना' आरम्भ की है, जिसके तहत स्वच्छतम प्राथमिक तथा मिडल स्कूलों को पुरस्कृत किया जायेगा। योजना के तहत वर्ष 2009–10 के लिए 62 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य की 253 ग्राम पंचायतों को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है जबकि गत वर्ष 245 पंचायतों को सम्मानित किया गया था। 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रदेश की कुल 3243 ग्राम पंचायतों में से 2097 ग्राम पंचायतों (64 प्रतिशत) को 'खुले में शौच' से मुक्त घोषित किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में 37 हजार करोड़ का निवेश

प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरण मित्र एवं सतत् औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। प्रदेश के लिए 7 जनवरी, 2003 से स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के परिणामस्वरूप नवम्बर, 2009 तक प्रदेश में 995 मध्यम / बड़ी इकाइयां, 11654 लघु औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत हुई जिसमें कुल 37,717.32 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है तथा इनमें 4 लाख 43 हजार 159 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। सरकार इस पैकेज को मार्च 2020 तक बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास कर रही है तथा इस मामले को भारत सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी इस औद्योगिक पैकेज को मार्च 2013 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। आवासीय अधोसरंचना के सृजन तथा बद्दी में व्यापार केन्द्र की स्थापना पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ के साथ परवाणू को भी 'सिटी गैस वितरण प्रणाली' में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(पृष्ठ 8 पर जारी)

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान 611 किलोमीटर मोटरयोग्य नई सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है तथा 139 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 2947 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है जबकि 259 पंचायतों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 1472 किलोमीटर है।